सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक 273 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शुक्रवार 13 नवम्बर, 2026
मूल्य ₹ 3/-



संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है।
–जवाहरलाल नेहरु



पंत पहले टेस्ट के लिए... 7 | पश्चिम बंगाल में गठबंधन की... 3 | पीडीए में हर समाज के पीड़ित... 2

चेहरा आजाद-ओवैसी का, चाल किसकी?

विपक्ष की काट या बीजेपी का हथियार?

» बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने लड़ा था 20 सीटों पर चुनाव

» राजद के लिए कहर साबित हुए थे ओवैसी

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने जिस भीम-मीम एकता के दम पर उत्तर प्रदेश की सियासत में नया अध्याय लिखने का दावा किया है क्या जनता उसे सचमुच नया विकल्प मान रही है? या फिर मतदाताओं के मन में यह सवाल है कि पहले से मौजूद राजनीतिक दलों और गठबंधनों के बीच एक और मोर्चा बनाने से आखिर हासिल क्या होगा?

स्थानीय स्तर पर लोगों से बातचीत में इस गठबंधन को लेकर उत्साह सीमित दिखाई दे रहा हैं और बात गहरी हो रही है। जनता इस गठबंधन को हाल के दिनों में हुए बिहार चुनाव के रिजल्ट से भी जोड़कर देख रही है और कह रही है कि यूपी में भी कहीं बिहार जैसी स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही। सवाल जो हवा में तैर रहा है और हर बार यही पूछता हुआ लौट रहा है कि इस गठबंधन का मास्टर माइंड कौन है?



आजाद-ओवैसी की जोड़ी पर सवाल

2020

के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमांचल की राजनीति में ऐसा दखल दिया कि राजद के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई।

ओवैसी के आग उगलते भाषण और...

ओवैसी की राजनीति में मुस्लिम समुदाय के अधिकार प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल प्रमुखता से उठते हैं। लेकिन जब चुनावी मंचों पर बहस विकास रोजगार और सामाजिक न्याय से हटकर हिंदू-मुस्लिम पहचान के टकराव में बदलती है तो उसका असर केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रहता। राजनीतिक बयानबाजी अगर धार्मिक पहचान के आधार पर मतदाताओं को लामबंद करने लगे तो ध्रुवीकरण की जमीन तैयार हो सकती है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को चुनावी लाभ मिलने की आशंका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यानी जिस मोर्चे का दावा बीजेपी को रोकने का है उसकी चुनावी रणनीति और भाषणों की शैली को लेकर ही यह बहस खड़ी हो रही है कि कहीं विपक्षी मतों का बंटवारा और धार्मिक ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए राजनीतिक अवसर तो नहीं बना देगा? ओवैसी इसे मुस्लिम प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई बता सकते हैं, चंद्रशेखर इसे दलितों और वंचितों की हिस्सेदारी का अभियान कह सकते हैं। मगर मतदाता केवल घोषणाओं से फैसला नहीं करता। वह यह भी देखता है कि उसके रोजमर्रा के सवालों का जवाब किसके पास है। यूपी की राजनीति में नारे बहुत सुने गए गठबंधन भी बहुत बने। लेकिन जनता के मन में जगह बनाने के लिए केवल दो चर्चित चेहरों का साथ आना काफी नहीं। उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि यह मोर्चा सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ नई चुनावी लकीर नहीं खींच रहा, बल्कि रोजगार, शिक्षा, महंगाई कानून-व्यवस्था और विकास पर भी ठोस जवाब रखता है। वरना 403 सीटों का दावा सुर्खियों में तो रहेगा लेकिन जनता के दरबार में उसकी असली परीक्षा बाकी ही रहेगी।

बीजेपी की रणनीति के लिए विपक्षी बिखराव का सवाल

विपक्षी राजनीति की एक पुरानी समस्या है सामाजिक आधारों का बिखराव और सीटों पर आपसी प्रतिस्पर्धा। अगर अलग-अलग विपक्षी दल एक ही विधानसभा क्षेत्र में समान मतदाता समूहों को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे तो मतों का विभाजन हो सकता है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को फायदा मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा सूरतेहाल में बीजेपी को लाभ मिलने की आशंका केवल मुस्लिम वोटों के विभाजन से नहीं जुड़ी है। अगर चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण की दिशा में जाता है तो उसका प्रभाव दूसरे समुदायों के मतदान व्यवहार पर भी पड़ेगा। हर कोई जानता है कि औवैसी के आग उगलते भाषण, आक्रामक तेवर और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का फायदा बीजेपी को मिलता है। पूर्व में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि एआईएमआईएम ने बिहार में मुस्तैदी से चुनाव लड़ा। जैसे सपा ने औवैसी को यूपी में भाव नहीं दिया ठीक उसी प्रकार से राजद ने बिहार में औवैसी को भाव नहीं दिया। नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि राजद को औवैसी की वजह से राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा और वोटिंग ट्रेंड में भी औवैसी के भाषणों के बाद बदलावा आया।

बिहार में ओवैसी की एंट्री, राजद को चोट और भाजपा को बढ़त

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमांचल की राजनीति में ऐसा दखल दिया कि राजद के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई। एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और पांच सीटें जीत लीं। उसका कुल वोट प्रतिशत भले ही करीब 1.3 प्रतिशत रहा, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में उसका प्रभाव कहीं अधिक केंद्रित था। यही उसकी असली राजनीतिक ताकत बनी। जोकिहाट इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा। यहां राजद को एआईएमआईएम उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर बायसी में एआईएमआईएम ने भाजपा को हराया जबकि राजद उम्मीदवार को 38 हजार से अधिक वोट मिले। यानी ओवैसी का असर हर सीट पर भाजपा के पक्ष में नहीं गया लेकिन कई सीटों पर विपक्षी वोटों के बंटवारे ने महागठबंधन की मुश्किलें जरूर बढ़ाईं। बहादुरगंज, कोचाधामन और अमौर में भी एआईएमआईएम की जीत ने सीमांचल में उसके स्वतंत्र जनाधार का संकेत दिया। चुनाव का अंतिम परिणाम भी गौर करने लायक है। भाजपा-जदयू के नेतृत्व वाले एनडीए ने 125 सीटें जीतीं, जबकि राजद-कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया। राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बना लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से गठबंधन पीछे रह गया। उत्तर प्रदेश के लिए बिहार का संदेश साफ है जब विपक्षी खेमे के भीतर ही वोटों की हिस्सेदारी को लेकर मुकाबला खड़ा होता है तो उसका लाभ सत्तारूढ़ गठबंधन को ही मिलता है। ओवैसी और आजाद का नया मोर्चा यदि सपा-कांग्रेस के परंपरागत मतदाताओं में सेंध लगाता है तो भाजपा को वैसा ही अवसर मिल सकता है। हालांकि बिहार का परिणाम उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा यह तय नहीं यहां जातीय समीकरण उम्मीदवार और स्थानीय मुद्दे अलग हो सकते हैं।

पीडीए में हर समाज के पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग हो रहे हैं शामिल : अखिलेश

» सपा प्रमुख बोले- पांच प्रतिशत अहंकारियों और 95 प्रतिशत पीडीए के बीच मुकाबला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर एकबार फिर प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सनातन धर्म की आड़ में अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे और दान में कथित चोरी का मामला उठाते हुए सवाल किए।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोपालकों को लेकर मुख्यमंत्री की कथित टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए इसे भगवान श्रीकृष्ण और सनातन धर्म का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि 2024 और 2026 की हार से मुख्यमंत्री घबरा गए हैं। अब चुनाव पांच प्रतिशत अहंकारियों, वर्चस्ववादियों और



प्रभुत्ववादियों बनाम 95 प्रतिशत पीडीए के बीच होगा। पीडीए में हर समाज के पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग शामिल हो रहे हैं। इसी कारण इसका जनाधार 85 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सनातन धर्म की आड़ में अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे और दान में कथित चोरी का मामला उठाते हुए सवाल किए। साथ ही वाराणसी में पाल समाज के लोगों पर लाठीचार्ज और राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा के कथित अपमान का भी आरोप लगाया।

कमजोर व्यक्ति अनैतिक सहारा तलाशने लगें हैं

सपा अध्यक्ष ने प्रदेश में एक अन्य व्यक्ति को बुलाए जाने पर भी मुख्यमंत्री को घेरा। आरोप लगाया कि दोनों की वेशभूषा, भाषा और भगवान राम-कृष्ण को लेकर टिप्पणियों में समानता है। उन्होंने कहा कि कमजोर व्यक्ति अनैतिक सहारा तलाशने लगता है। मुख्यमंत्री में साहस और सामर्थ्य है तो समाज को बांटने वाले बयान देने वालों को प्रदेश में आने से रोकें। अखिलेश ने नसीहत दी कि सनातनी वस्त्र पहनकर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपने शब्दों और व्यवहार में मर्यादा रखनी चाहिए।

इनाम की राशि दोषी अधिकारियों कंपनी से वसूले आयोग

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के डुप्लीकेट वोटर खोजने वालों को ईनाम की घोषणा के मुद्दे पर कहा कि ये भी घोषणा होनी चाहिए कि पुरस्कार की राशि की दोगुनी राशि चुनाव आयोग के दोषी उच्चाधिकारियों या डुप्लीकेट वोटर न पकड़ पाने वाला फॉल्टी सॉफ्टवेयर डेवलप करनेवाली कंपनी से वसूली जाएगी। अगर ये नहीं हुआ तो जनता के टैक्स का पैसा ही जनता को देकर एक और चपत लगाई जाएगी।

सपा प्रमुख ने आजम खां की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। अखिलेश ने प्रशासन से उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने की अपील की। अखिलेश यादव ने लिखा, ये समाचार मिला है कि आदरणीय आजम खां साहब को प्रशासन द्वारा गाजियाबाद की डासना जेल से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। कोई भी लापरवाही न बरती जाए।

ओवैसी पूछते थे, अब्दुल सीएम कब बनेगा? अब उन्होंने तय किया वह दलित की दरी बिछाएगा : रोहिणी घावरी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के सामाजिक परिवर्तन मोर्चे पर डॉ. रोहिणी घावरी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि कल तक वह सवाल करते थे कि अब्दुल मुख्यमंत्री कब बनेगा और कब तक दरी बिछाएगा, लेकिन अब खुद एक दलित नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब अब्दुल दलितों के पीछे जाकर दरी बिछाएगा। रोहिणी ने कहा कि दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुए, लेकिन तीनों जगह इनका नतीजा शून्य रहा। उन्होंने मोर्चे को चुनौती देते हुए कहा कि अगर गठबंधन एक भी सीट जीत गया तो वह उनकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। उन्होंने ओवैसी और चंद्रशेखर पर दलितों और मुसलमानों को राजनीतिक रूप से गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दोनों को भाजपा की बी टीम बताया। डॉ. रोहिणी घावरी ने स्विट्जरलैंड से डॉक्टरेट



की पढ़ाई की है। वह दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय रहती हैं। चंद्रशेखर से उनका विवाद निजी संबंधों को लेकर है। रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने शादी का भरोसा देकर उनका शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत भी की है। इसी मामले से वह चर्चा में आई थीं।

अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व ही रहेंगे : ओवैसी



एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन के मंच से सपा और अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश के नेतृत्व, मुस्लिम राजनीति और अयोध्या में राम मंदिर जाने के कार्यक्रम पर सवाल उठाए। आजम खां के बहाने सपा के मुस्लिम सांसदों और विधायकों को घेरा। अखिलेश पर तंज कसते हुए ओवैसी ने अमीर मीनाई का शेर पढ़ा, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता-आहिस्ता, निकलता आ रहा है तेरा चेहरा आहिस्ता-आहिस्ता। कहा, अखिलेश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व ही रहेंगे। उन्होंने सपा अध्यक्ष की राजनीतिक विरासत और उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को लगी गोली का जिक्र करते हुए कहा कि गोली लगने का दर्द आज भी उनके भाई की कमर में है। चंद्रशेखर ने कहा कि दलित उत्पीड़न पर विपक्ष चुप रहता है।

बच्चों को शिक्षित करना ही मेरा अपराध था : आजम खां

» ईडी की अभिरक्षा में लखनऊ जाने के दौरान बोले सपा नेता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां ने ईडी की अभिरक्षा में एक बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि बच्चों को शिक्षा देना अपराध था। आजम खां ने बताया कि उन्होंने एक विश्वविद्यालय और कई स्कूल बनाए। उनके अनुसार, एक मुस्लिम द्वारा शिक्षा का मंदिर बनाना ही गलती थी। उन्होंने अपने इन प्रयासों को अपराध बताया। ईडी कोर्ट से मिली चार दिन की रिमांड पर आजम खां को लखनऊ लेकर जा रही है।



जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आजम खां को ईडी की विशेष अदालत ने चार दिन की रिमांड पर भेजा है। बृहस्पतिवार की शाम करीब साढ़े सात बजे ईडी की टीम फोर्स के साथ डासना स्थित जिला कारागार पहुंची और आजम खां को अपनी अभिरक्षा में लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि ईडी के अधिकारियों ने जिला कारागार में कोर्ट के आदेश तामील कराए। ईडी ने आजम खां से पूछताछ के लिए अदालत में अर्जी लगाकर पांच दिन की रिमांड मांगी थी। पीठासीन अधिकारी अवनीश कुमार के अवकाश पर होने से संबंद्ध कोर्ट में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने रिमांड पर भेज दिया। आजम को ईडी अदालत ने एक नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेजा था, 13 नवंबर को जेल से अदालत में पेश होना था, उसके पहले ही ईडी ने अदालत से चार दिन की रिमांड पर ले लिया।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी



संसद में सरकार को घेरेंगे, वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे उठाएंगे पवार : संजय सिंह

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई । आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने शुक्र वार को कहा कि एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार संसद में कथित वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। पवार के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, सिंह ने कहा कि वह मुख्य रूप से पवार का हाल-चाल जानने के लिए उनसे मिलने गए थे।

उन्होंने बताया कि पवार ने संसद के विशेष सत्र की शुरुआत के बारे में पूछा और दिल्ली में कथित तौर पर वोट चोरी होने और मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के मामले की जानकारी मांगी। सिंह ने कहा,

आप नेता ने पवार के साथ की बैठक

एनसीपी के विलय पर कोई चर्चा नहीं

जब उनसे शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के दो गुटों के विलय की संभावना के बारे में पूछा गया, तो आप सांसद ने कहा, इस बारे में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि, हमने वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर जरूर चर्चा की है, जो आजकल उठाए जा रहे हैं। जहां तक संसदीय सत्र की बात है, चूंकि उन्होंने पूछा था कि यह कब शुरू होगा और इसकी कार्यवाही कैसी होगी, तो मुझे विश्वास है कि पवार साहब संसद में भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएंगे।



हमने महाराष्ट्र की राजनीति के कुछ पहलुओं और एमएलसी चुनावों के नतीजों पर भी चर्चा की। यह एक सुखद और अच्छी मुलाकात रही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शरद पवार साहब जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और उसी ऊर्जा के साथ अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाते रहें और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करते रहें, जिस तरह से उन्होंने हमेशा काम किया है।

संसद में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पर चल रही राजनीतिक बहस के संदर्भ में, सिंह ने दावा किया, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास जरूरी संख्या बल नहीं है। जहां तक महिला आरक्षण विधेयक की बात है, तो हम इसे पहले ही पारित कर चुके हैं। अगर वे महिला आरक्षण विधेयक को लागू करना चाहते हैं, तो उन्हें इसे मौजूदा संख्या बल के आधार पर लागू करना चाहिए। परिसीमन के लिए एक उचित प्रक्रिया होती है, जिसका पालन किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में गठबंधन की संभावना पर विचार

वामपंथी पार्टियां फिर एकजुट होने के पक्ष में

टीएमसी व कांग्रेस से फिर हो मजबूती की बात

- भाजपा को हटाने के लिए जनमुद्दे उठाने होंगे
- सीपीएम का इससे से इनकार नहीं
- महासचिव एमए बेबी बोले- राहुल गांधी के पीएम चेहरे पर चर्चा का वक्त नहीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कभी पश्चिम बंगाल में 24 से ज्यादा साल तक लगातार सत्ता में रहे वामपंथी दल एकबार फिर वहां की सत्ता में आने का सपना संजो रहे हैं। कांग्रेस को इस पूर्वी राज्य से बेदखल कर वहां पर कई वर्ष तक शासन करने वाली वामपंथी सरकार को कांग्रेस से ही अलग हुई ममता बनर्जी ने जोरदार झटके देते हुए सत्ता हथिया ली थी। पर वक्त की कहानी ने 15 साल बाद ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार को धूल चटाई और उसे भाजपा ने सत्ता से दूर किया।

अब इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच कई राज्यों में राजनीतिक विरोधाभासों के बावजूद सीपीएम ने विपक्षी एकता की संभावनाओं को खुला रखा है। पार्टी के महासचिव एमए बेबी का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना और मौजूदा सरकार की नीतियों का मुकाबला करना है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ संभावित गठबंधन पर फैसला राज्य इकाई पर छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को मौजूदा स्थिति से बाहर निकालने के लिए पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष के नेता और INDIA गठबंधन के प्रमुख चेहरों में से एक बताया, लेकिन साझा नेतृत्व या प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर अभी चर्चा को गैरजरूरी माना।



केरल में कांग्रेस और सीपीएम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी

केरल में कांग्रेस और सीपीएम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में सीपीएम और टीएमसी। ऐसे विरोधाभासों के बीच विपक्षी एकता कितनी व्यावहारिक है? यह हमारे राष्ट्रीय जीवन का कठिन दौर है और ऐसे समय में कभी-कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। हमने केरल में कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ अपने मतभेद कभी नहीं छिपाए हैं। करीब तीन दशक पहले भी वामपंथ ने एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सांप्रदायिक सोच को सत्ता से बाहर रखने के लिए यूपीए सरकार के गठन में कांग्रेस का समर्थन किया था।

राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में से एक

क्या राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के स्वाभाविक नेता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है? क्या गठबंधन को साझा नेता या चेहरे की घोषणा कर देनी चाहिए? राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा राजनीतिक घटक है। इसलिए गठबंधन में उनकी भूमिका स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है और उन्हें मान्यता भी प्राप्त है। हालांकि, अभी साझा नेता या राष्ट्रीय चेहरे की घोषणा जैसी तकनीकी चर्चाओं में उलझने का समय नहीं है। इस समय प्राथमिकता लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए विपक्ष को एकजुट करने की होनी चाहिए।

विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को बड़ा आंदोलन बनाने में सफल रहेगा

महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण संकट को लेकर लोगों में स्पष्ट नाराजगी है। यहां तक कि सरकार का समर्थन करने वाले लोग भी इन वास्तविकताओं को स्वीकार करते हैं। जंतर-मंतर पर पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन युवाओं के गुस्से से प्रेरित था। वे ऐसी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जिसने उनकी शिक्षा और रोजगार संबंधी आकांक्षाओं को कुचला है। आज समाज के अधिक से अधिक वर्ग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पहले जो डर का माहौल था, वह काफी हद तक खत्म हुआ है। लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में देश अलग-अलग वर्गों की भागीदारी वाले और बड़े विरोध प्रदर्शनों का गवाह बनेगा।



जनता के अधिकारों की लड़ाई में सबसे आगे

हम हमेशा जनता के अधिकारों की लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं। इस गिरावट के कई कारण हैं और उनसे उबरने के लिए हम लगातार सचेत प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वामपंथ जिस राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करता है, उसे चुनावी आंकड़ों, संगठनात्मक ताकत और राजनीतिक ढांचे से कहीं आगे भी व्यापक समर्थन और स्वीकार्यता मिल रही है।

सीपीएम पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ राजनीतिक गठबंधन की संभावना देखती है?

ऐसे मामलों पर विचार करके फैसला लेना राज्य इकाई का काम है। केंद्रीय नेतृत्व उचित सुझाव देने के लिए हमेशा उपलब्ध है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राज्य स्तर पर भी बीजेपी के सत्ता में आने के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। पश्चिम बंगाल को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए हर स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। हम इससे इंकार नहीं कर रहे हैं।

सीपीएम का भविष्य का विजन बनेगा

हमने केंद्रीय और राज्य स्तर पर कई बैठकें की हैं। इनमें पश्चिम बंगाल और केरल की विस्तारित राज्य कमेटी की बैठकें भी शामिल हैं। हम अपनी सीमाओं के साथ-साथ अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर भी सजग हैं। हमारी स्पष्ट सोच है कि बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में लाया जाना चाहिए। मौजूदा चुनौतियों के अनुरूप राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टिकोण में भी बदलाव करने होंगे। इस दिशा में बदलाव शुरू हो चुके हैं। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों में वामपंथ की भूमिका इसका प्रमाण है।

चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल हैं?

मीडिया में हुए खुलासों और चुनाव आयोग द्वारा अपने पहले के फैसलों से पीछे हटने की घटनाओं से स्पष्ट है कि एसआईआर की पूरी कवायद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई थी। इस सरकार का लगभग हर कदम जनता की इच्छा को बाधित करने की दिशा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने स्पष्ट कहा था कि स्वतंत्र चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनावों के लिए अनिवार्य है। उस फैसले को दरकिनार करने की कोशिश का उद्देश्य आयोग को कार्यपालिका के अधीन संस्था में बदलना था। हमारा विरोध केवल किसी व्यक्ति के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं है। हमारी मांग स्वतंत्र चुनाव आयोग के अधीन निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की है। वामपंथ की संसद में मौजूदगी सीमित हो गई है। राष्ट्रीय राजनीति में उसका प्रभाव घटने की क्या वजह है?

क्षेत्रीय स्तर पर मतभेदों के बावजूद राजनीतिक दल साझा मंचों पर साथ आएं

इंडिया गठबंधन केवल चुनावी व्यवस्था नहीं है। यह उस लोकतांत्रिक स्पेस को फिर से हासिल करने का मंच है, जिसे देश में व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया गया है। चुनाव इस बड़े संघर्ष का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमारा काम निश्चित रूप से चुनावों पर भी असर डालेगा। क्षेत्रीय स्तर पर मतभेदों के बावजूद राजनीतिक दल साझा मंचों पर साथ आए हैं। हमारी समझ है कि किसी राज्य में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी को दूसरे दलों को साथ लेकर चलने की पहल करनी चाहिए, ताकि बंटे हुए विपक्ष का फायदा एनडीए को न मिले। एसआईआर के खिलाफ संयुक्त विरोध प्रदर्शनों ने विपक्ष को इस दिशा में एकजुट करना शुरू किया है। हालांकि, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_SanjayS

जिद... सच की

वीवीआईपी लोगों की भी समाज के प्रति जवाबदेही

राष्ट्रति द्रौपदी मुर्मु की टिप्पणी कि सच्चा सितारा रोशनी फैलाता है, अंधेरापन नहीं, आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण होने के साथ ही सितारों और सेलिब्रिटिज को समाज के प्रति जवाबदेही समझने का संकेत भी है। दर असल हो रहा है कि पैसे की चकाचोंध में सेलिब्रिटिज समाज के प्रति जवाबदेही से मुहं मोड़ते दिखाई देते हैं।

विज्ञापनों के प्रति सेलिब्रिटिज या वीवीआईपी का मोह जगजाहिर है। वे पैसे के लिए कु छ ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने लगे हैं जो समाज के लिए हानिकारक हैं। हालांकि अदालतों द्वारा समय-समय पर उन्हें फटकार मिलती है। तो कु छ बड़े कलाकार तो दूरी बना लेते हैं पर अधिकांशत: उसके मोह में पड़े रहते है। अब इस मामले में जवाबदेही को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की टिप्पणी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अपने उत्पादों को बेचने के लिए सेलिब्रिटिज का उपयोग सबसे अधिक किया जाता रहा है। विज्ञापनदाता जानते हैं कि लक्षित उपभोक्ता तक पहुंचने में सेलिब्रिटिज की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लोग सेलिब्रिटिज पर विश्वास करते हैं और विज्ञापनदाता कंपनियां इसी का लाभ अपने उत्पादों को बाजार दिलाने में करते आये हैं। इसीलिए राष्ट्रति द्रौपदी मुर्मु की टिप्पणी कि सच्चा सितारा रोशनी फैलाता है, अंधेरापन नहीं, आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण होने के साथ ही सितारों और सेलिब्रिटिज को समाज के प्रति जवाबदेही समझने का संकेत भी है। दर असल हो रहा है कि पैसे की चकाचोंध में सेलिब्रिटिज समाज के प्रति जवाबदेही से मुहं मोड़ते दिखाई देते हैं।

जब आम जन का सेलेब्रिटिज का भरोसा है तो सेलिब्रिटिज की भी इस भरोसे को बनाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। दरअसल सेलिब्रिटिज को उत्पाद के साथ देखकर आमआदमी आंख मींच कर भरोसे के सहारे खरीदारी करता है। वह उस उत्पाद और सेलिब्रिटिज द्वारा किये जा रहे वादे को सत्य समझता है। ऐसे में सेलिब्रिटी का समाज या लक्षित वर्ग के प्रति और अधिक जिम्मेदारी बन जाती है। विकेता या निर्माता अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान देता है। इसलिए वह अपने उत्पाद के गुणगान अधिक ही करने लगता है तो सेलिब्रिटी के विज्ञापन के सहारे अतिशयोक्तिपूर्ण दावें करने लग जाते हैं। यहां तक कि कई विज्ञापन के दावें तो सत्य के आसपास भी नहीं होते जैसा कि अक्षय कुमार का डॉबर च्यवनप्राश को लेकर विज्ञापन। यह तो एक उदाहरण मात्र है। आज तो सेरोगेट विज्ञापनों का दौर भी चल निकला है। शाहरुख , अजय देवगन और टाइगर का इलायची का विज्ञापन सबके सामने है जिसके माध्यम से छद्म रुप से प्रतिबंधित पान मसाला का विज्ञापन किया जा रहा था। इसी तरह के अनेक विज्ञापन हमारे सामने हैं। हांलाकि इसमें कोई दो राय नहीं कि निर्माता अपने उत्पाद का विज्ञापन करने के लिए सेलिब्रिटिज को बहुत अधिक पेमेंट किया जाता है और इस पेमेंट के चक्कर में सेलिब्रिटिज समाज के प्रति अपने दायित्व और कानूनी प्रावधानों को भी दरकिनार कर देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दुखती रग पर हाथ रखते हुए 72 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पिछले माह सितंबर में आयोजित समारोह में आमआदमी का दर्द सामने रखा।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

संपादक को पत्र...

सर, मैंने कई तरह के अखबार पढ़े , चैनल देखे हैं, लेकिन आपका अखबार व चैनल एकदम अलग लगा। आपके अखबार व यूट्यूब चैनल हर खबर की तह तक जाता है जो बहुत ही अलग बात है इस अखबार की। इसमें आप हर बात को बड़ी सच्चाई के साथ पेश करते हैं। आपका का नाम भी अलग है। वाकई 4 पीएम से हमेशा अलग खबरें ही मिलती हैं हर रोज। साथ ही इस 4पीएम डिजिटल होने के कारण कहीं भी आसानी से पढ़ सकते हैं। इस 8 पेज के अखबार में सभी चीजें मिल जाती हैं जैसे एक बड़े अखबार में जैसे अजब-गजब, ट्विट, व चुटकुले के साथ कहानियां कुल मिलाकर गंभीर खबरों के साथ रोचक भी है आपका अखबार व यूट्यब चैनल।

राजेश अग्रवाल , आलमबाग

सर, मैं कु छ सालों से आपके यूट्यूब चैनल व अखबार के बारे में नहीं सुन रखा था। अब जबसे मै इससे जुड़ा हूं और इसके बारे में जाना तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह अखबार व चैनल सबसे उम्दा लगा। सबसे अलग तरह की खबरें मिलती है 4 पीएम में। खासकर अखबार की जो लिखने व यूट्यूब चैनल में जो बोलने की शैली है वो सभी और अखबारों से एकदम जुदा है। साथ ही सभी खबरों की हेडलाइन काफी आकर्षक होती हैं। आपके अबखार का जो स्लोगन है जिद सच की वह आपकी खबर के हिसाब से एकदम सटीक हैं। आपका अखबार एकदम सच्ची खबरे प्रकाशित करता हैं। बिना किसी के डर के। ऐसे अखबार को मेरा सलाम।

विशाकुमार, गोमतीनगर

धर्म के शोर में दबते जनहित के मुद्दे!

धर्मेन्द्र सिंह 'बाँकीपुरी'

जब आस्था राजनीति का हथियार बन जाए, तो जनता के असली मुद्दों का क्या होगा? भारत आस्थाओं का देश है। यहाँ धर्म केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और जीवन-दर्शन का हिस्सा है। मंदिर की घंटियाँ, मस्जिद की अजान, गुरुद्वारे का कीर्तन और गिरजाघर की प्रार्थनाएँ इस देश की विविधता को स्वर देती रही हैं। यही विविधता भारतीय समाज की विशिष्ट पहचान है। लेकिन आज एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। जिस धर्म का उद्देश्य मनुष्य को नैतिकता, करुणा और सद्भाव की ओर प्रेरित करना है,

वही धर्म जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का माध्यम बनने लगे, तो समाज की प्राथमिकताएँ किस दिशा में जाती हैं? यह सवाल आस्था का नहीं, आस्था के राजनीतिक इस्तेमाल का है। देश में जब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महँगाई और किसानों की आय जैसे प्रश्न समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हों, तब सार्वजनिक विमर्श में धार्मिक पहचान और उससे जुड़े विवादों का अत्यधिक प्रभाव चिंता पैदा करता है। आखिर ऐसा क्यों है कि धर्म के नाम पर समाज में जितनी तीव्र बहस होती है, उतनी तीव्रता से विद्यालयों की बदहाली, अस्पतालों की अव्यवस्था और बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर चर्चा नहीं होती?

आस्था का सम्मान या आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल?

धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है। संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक ध्रुवीकरण में बुनियादी अंतर है।धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने का अधिकार देती है, जबकि धार्मिक ध्रुवीकरण समाज को धार्मिक पहचान के आधार पर परस्पर विरोधी समूहों में बाँट सकता है। लोकतांत्रिक राजनीति में धार्मिक समुदायों की सांस्कृतिक चिंताओं पर चर्चा स्वाभाविक है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब धार्मिक पहचान को नागरिकों के बीच अविश्वास पैदा करने या सार्वजनिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजनीति का दायित्व समाज को दिशा देना है, उसे स्थायी संदेह और टकराव में उलझाए रखना नहीं।किसी नागरिक की धार्मिक पहचान चाहे जो हो, उसे रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, सुलभ उपचार चाहिए और सम्मानजनक जीवन चाहिए।भूख का कोई धर्म नहीं होता। बेरोजगारी किसी जाति या संप्रदाय का परिचय पूछकर घर में प्रवेश नहीं करती। बीमारी अस्पताल पहुँचने से पहले मरीज की धार्मिक पहचान नहीं देखती।फिर इन साझा समस्याओं पर समाज की एकजुटता उतनी मुखर क्यों नहीं दिखाई देती, जितनी धार्मिक विवादों के समय दिखाई देती है?

बेरोजगार युवा और पहचान की राजनीति

भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी संभावनाओं में शामिल है। लेकिन युवाओं की आकांक्षाओं और उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बीच अंतर एक गंभीर चुनौती है।एक युवा वर्षों पढ़ाई करता है। परिवार अपनी सीमित आय का बड़ा हिस्सा उसकी शिक्षा पर खर्च करता है। माता-पिता अपने सपनों को बच्चों के भविष्य से जोड़ देते हैं। लेकिन जब शिक्षा पूरी होने के बाद भी सम्मानजनक रोजगार नहीं मिलता, तब निराशा केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की होती है।ऐसे समय में राजनीति से अपेक्षा होती है कि वह रोजगार सृजन, कौशल विकास, उद्योगों के विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर चर्चा करे। धार्मिक पहचान से जुड़े प्रश्नों का अपना स्थान हो सकता है, लेकिन वे रोजगार नीति का विकल्प नहीं बन सकते। युवा को अपनी आस्था पर गर्व करने का पूरा अधिकार है। साथ ही उसे अपने भविष्य के बारे में सरकार से प्रश्न पूछने का भी उतना ही अधिकार है।आस्था और रोजगार एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में पहचान की राजनीति को आजीविका के प्रश्नों पर स्थायी प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए।

मंदिर-मस्जिद की बहस और अस्पताल-विद्यालय का सवाल

किसी समाज की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन केवल उसके धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों से नहीं किया जा सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाएँ भी उसकी प्रगति के अनिवार्य पैमाने हैं।एक ओर धार्मिक स्थलों और परंपराओं को लेकर व्यापक सार्वजनिक बहस होती है, दूसरी ओर अनेक क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपलब्धता और स्वास्थ्य



सेवाओं तक पहुँच जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।यहाँ धार्मिक स्थलों के निर्माण या संरक्षण का विरोध नहीं है। समाज को अपनी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रखने का अधिकार है।लेकिन प्रश्न प्राथमिकताओं के संतुलन का है।क्या किसी गाँव में धार्मिक आयोजन की चर्चा के साथ वहाँ के विद्यालय की स्थिति पर भी उतनी ही गंभीरता से बातचीत होती है? क्या धार्मिक पहचान पर बहस करने वाले नागरिक अपने क्षेत्र के अस्पताल में चिकित्सकों और दवाओं की उपलब्धता को भी सार्वजनिक प्रश्न बनाते हैं? एक अच्छे समाज में आस्था और नागरिक सुविधाओं के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। दोनों का अपना स्थान है।मंदिर और मस्जिद मनुष्य की आस्था से जुड़े हैं, जबकि विद्यालय और अस्पताल उसके जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से।इनमें से किसी एक का सम्मान दूसरे की उपेक्षा का कारण नहीं बनना चाहिए।

धार्मिक ध्रुवीकरण और लोकतंत्र की जवाबदेही

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता की प्रश्न पूछने की क्षमता है। जनता सरकार चुनती है, इसलिए उसे सरकार के निर्णयों, नीतियों और उपलब्धियों की समीक्षा करने का भी अधिकार है।लेकिन जब राजनीतिक विमर्श धार्मिक पहचान के इर्द-गिर्द अत्यधिक केंद्रित हो जाता है, तब शासन की जवाबदेही से जुड़े प्रश्नों को अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाता। लोकतंत्र में सरकार का मूल्यांकन केवल उसके सांस्कृतिक या वैचारिक कार्यक्रमों से नहीं, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं, आर्थिक अवसरों, कानून-व्यवस्था और नागरिक अधिकारों के आधार पर भी होना चाहिए।यह जिम्मेदारी किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक समर्थन में बदलने की प्रवृत्ति का मूल्यांकन सभी दलों और संगठनों के संदर्भ में समान लोकतांत्रिक मानकों पर होना चाहिए। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह केवल धार्मिक विवादों पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित न रहे, बल्कि जनहित के प्रश्नों पर ठोस विकल्प और समाधान प्रस्तुत करे। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष, दोनों की राजनीतिक सफलता से अधिक महत्वपूर्ण नागरिकों का कल्याण है।

सोशल मीडिया : संवाद का मंच या विभाजन का माध्यम?

डिजिटल माध्यमों ने नागरिकों को अभिव्यक्ति की अभूतपूर्व सुविधा दी है। लेकिन इसी व्यवस्था में उत्तेजक, भ्रामक और भावनात्मक सामग्री के तेजी से फैलने का जोखिम भी मौजूद है।धार्मिक पहचान से जुड़े छोटे विवाद भी कभी-कभी व्यापक सामाजिक तनाव का रूप ले सकते हैं। अधूरी सूचनाएँ, संदर्भ से काटे गए वीडियो और अपुष्ट दावे लोगों के बीच अविश्वास बढ़ा सकते हैं।ऐसे वातावरण में जिम्मेदार पत्रकारिता और नागरिक विवेक का महत्व बढ़ जाता है। समाचार माध्यमों का दायित्व केवल यह बताना नहीं है कि किसने किसके विरुद्ध क्या कहा। उन्हें यह भी पूछना चाहिए कि सार्वजनिक संसाधन कहाँ खर्च हो रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ किसे मिल रहा है और नागरिक सेवाओं में सुधार की वास्तविक स्थिति क्या है। जब शोर समाचार का स्थान लेने लगे, तब जनहित के प्रश्न पीछे छूटने का खतरा बढ़ जाता है।

धर्म का सम्मान, संविधान की मर्यादा

भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। साथ ही वह सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करता है। संविधान का अनुच्छेद 25 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन अंत:करण की स्वतंत्रता तथा धर्म के पालन, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसलिए धर्म और संविधान को एक-दूसरे के विरोध में खड़ा करना उचित नहीं है।वास्तविक चुनौती ऐसी सार्वजनिक संस्कृति विकसित करने की है, जिसमें नागरिक अपनी धार्मिक पहचान सुरक्षित रखते हुए दूसरे नागरिकों के समान अधिकारों का भी सम्मान करें।धर्म मनुष्य के निजी और सामुदायिक जीवन को अर्थ दे सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन का मूल्यांकन नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और सार्वजनिक कल्याण के आधार पर होना चाहिए। आखिर जनता के सवाल कौन पूछेगा? भारत को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने का अधिकार है।

बाल दिवस

बच्चों के पूर्ण विकास के लिए करता है प्रेरित



भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। नेहरू जी को बच्चों से बेहद लगाव था और उन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से पुकारा जाता था। उनके इसी प्रेम और बच्चों के प्रति समर्पण के कारण उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन बाल दिवस नेहरू जी की जयंती से 10 साल पहले ही मनाया जाना शुरू हो गया था उन्होंने बच्चों के विकास के लिए कई कदम उठाए। उनकी मौत के बाद, उनकी स्मृति में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने का फैसला लिया गया।



बाल दिवस कैसे मनाया जाता है?

बाल दिवस देश भर में अलग-अलग कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं और खेल आयोजित किए जाते हैं। इस दिन कई संगठन भी बच्चों के लिए खास कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है और उन्हें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। बाल दिवस समाज में बच्चों के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद करता है। इस दिन लोग बच्चों के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और बच्चों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रेरित होते हैं।

बाल दिवस का महत्व

बाल दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों के महत्व को उजागर करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बच्चे हमारे समाज का भविष्य हैं। यह दिन बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी एक अवसर है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार और सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार। बाल दिवस हमें बच्चों के प्रति समाज के दायित्व को याद दिलाता है। यह दिन हमें बच्चों के लिए एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमें बच्चों को प्यार, देखभाल और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह दिन हमें बच्चों के पूर्ण विकास के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल-कूद में सुधार लाना।

कब हुई शुरुआत

भारत में बाल दिवस मनाने की शुरुआत 1956 से हुई थी। उस समय इसे बाल दिवस के नाम से नहीं जाना जाता था बल्कि इसे बाल कल्याण दिवस के नाम से मनाया जाता था। 1956 में भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू कीं और इन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 14 नवंबर को बाल कल्याण दिवस मनाने का फैसला किया गया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू और बच्चे

पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे। वे बच्चों को देश का भविष्य मानते थे। उन्होंने हमेशा बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने बच्चों के लिए कई योजनाएं शुरू किए। नेहरू जी का मानना था कि बच्चों को एक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वे आगे चलकर देश का नाम रोशन कर सकें और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम कर सकें। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और 27 मई 1964 को उनके निधन तक वे इस पद पर बने रहे। उनके जन्मदिन पर हम उनकी वंदना करते हैं।

हंसना मना है

इंटरव्यू में एचआर -अच्छा आपका नाम पप्पू है? पप्पू-जी, इस गोले पर पप्पू ही नाम है मेरा... एचआर-बढ़िया, आपके लिए पहला सवाल है जावा के चार वर्जन क्या है, पप्पू उत्साह में बोला-आपको तो पता ही होगा, एचआर-हां, पर मुझे आप से सुनना है...पप्पू-ये आपने अच्छी बात की है और मुझे गाने का भी शौक है... इंटरव्यूर-मतलब, पप्पू-मर जावा, मिट जावा, लूट जावा और सदके जावा... इतना सुनते ही एचआर बोला- बहुत बढ़िया अब आप सीधे घर जावा...

गिरा दूंगा हर वो दीवार जो...तेरे मेरे बीच में आएगी...क्योंकि मेरा एक दोस्त जेसीबी चलाता है...

छात्र (भगवान से)-हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, अगर पास करदे तो क्या बात है!

वकील- हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द? पत्नी- मेरा चश्मा कहां है संगीता? वकील- तो इसमें मारने वाली क्या बात थी? पत्नी- मेरा नाम रंजना है, पूरा कोर्ट खामोश।

सरदार दुखी था। किसी ने पुछा- क्यों टेंशन में हो? सरदार- यार एक दोस्त को प्लास्टिक सर्जरी के लिए 2 लाख दिए, अब साले को पहचान नहीं पा रहा हूं।

कहानी — खुशबू की कीमत

एक भिखारी नंदा नगरी में खाने के लिए मांग रहा था। एक व्यक्ति कुछ रोटियां देता है। अब भिखारी सब्जी की तलाश में एक पंडाल में पहुंचता है। वहां भिखारी पंडाल के मालिक से सब्जी मांगता है। मालिक उसे भगा देता है। दुखी भिखारी किसी तरह मालिक की नजरों से बचते हुए पंडाल की रसोई में पहुंच जाता है। वहां उसे कई तरह की लजीज सब्जियां दिखती हैं। गर्म-गर्म सब्जियों से भाप निकल रही थी। भिखारी के मन में हुआ कि अगर रोटियों को इस भाप के ऊपर रख दिया जाए, तो सब्जी की खुशबू उनमें मिल जाएगी। और सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भिखारी रोटी पर सब्जी डालने की जगह, उन्हें सब्जी से निकलने वाले भाप के ऊपर रख देता है। तभी पंडाल का मालिक भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। भिखारी उससे कहता है कि मैंने सब्जी नहीं चुराई है। मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। मालिक कहता है कि अगर सिर्फ खुशबू ली है, तो उसकी भी कीमत चुकानी होगी। भिखारी कहता है, मालिक मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे कीमत चूकाऊं। मालिक उसे मुल्ला नसरुद्दीन के दरबार ले जाता है। नसरुद्दीन मालिक और भिखारी की बातों को सुनते हैं। मुल्ला कुछ देर सोचकर पंडाल मालिक से कहते हैं कि तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू के बदले पैसे चाहिए। जी हां। फिर मुल्ला मालिक से कहते हैं, तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत मैं स्वयं दूंगा। मालिक खुश हो जाता है। फिर नसरुद्दीन उसे बताते हैं, देखो, मैं तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। मुल्ला अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं और उन्हें खनखनाने लगते हैं। फिर उन सिक्कों को दोबारा जेब में डाल लेते हैं। यह सब देखकर पंडाल मालिक हैरान हो जाता है। वह मुल्ला से कहता है कि यह उन्होंने कैसी कीमत अदा की है। जवाब में मुल्ला कहते हैं, तुम्हारी सब्जी की खुशबू इस भिखारी ने ली थी। इसी वजह से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई है। अगर भिखारी ने सब्जी ली होती, तो तुम्हें सिक्के जरूर मिलते। मुल्ला का जवाब सुनकर पंडाल मालिक वहां से चला जाता है। भिखारी भी खुशी-खुशी अपने रास्ते निकल जाता है।

7 अंतर खोजें



जानिए कैसा रहेगा कल का दिन



पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद् हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष — कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी। व्यापार में नए सौदों से भारी मुनाफा हो सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे।

वृषभ — दफ्तर में वातावरण आपके पक्ष में रहेगा, काम आसान होगा। व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा धन लाभ संभव है। परिवार में सुख, शांति और सौहार्द बना रहेगा।

मिथुन — विरोधियों पर आपकी बढ़त बनी रहेगी, सफलता मिलेगी। व्यापार में नई रणनीति से बिक्री और मुनाफा बढ़ेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क — दफ्तर में अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित रखें। व्यापार में पैसों के लेन-देन में सतर्कता बरतें। बच्चों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी। श्री सूक्त का पाठ करें या सुनें।

सिंह — अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर होगा, तरक्की होगी। व्यापार में नए निवेश से बड़ा फायदा मिल सकता है। दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी।

कन्या — कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन शानदार रहेगा, तारीफ मिलेगी। व्यापार विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी। परिवार का पूरा सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा।

तुला — दफ्तर में आपकी बातों को तवज्जो मिलेगी, पद बढ़ेगा। व्यापार में नए अनुबंधों से अच्छा आर्थिक लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध काफी सुखद रहेंगे।

वृश्चिक — दफ्तर में गुप्त शत्रुओं की चाल से सावधान रहें। व्यापारिक फैसलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिजनों के साथ संवाद में संयम बरतें। फिजूलखर्च टालें, बजट बनाकर काम करें।

धनु — दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता की हर तरफ चर्चा होगी। व्यापार में बड़ा आर्थिक मुनाफा होने के योग हैं। दोस्तों और प्रियजनों के साथ सुखद समय बीतेगा।

मकर — वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से प्रोजेक्ट पूरा होगा। व्यापार में नई योजनाओं से मुनाफा बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली और सौहार्द रहेगा।

कुम्भ — भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम आसानी से बनेंगे। व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी और मुनाफा दिलाएंगी। घर में मांगलिक या धार्मिक कार्य की रूपरेखा बनेगी।

मीन — कार्यस्थल पर सतर्कता बरतें, विवादों से दूर रहें। व्यापारिक मामलों में उधारी देने से बचें। जीवनसाथी का सहयोग और सलाह काम आएगी।

न पंडित, न फेरे और न मंत्रों का जाप, मॉडर्न अंदाज में हुई काव्या मारन-अनिरुद्ध रविचंदर की शादी

अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ व को-ओनर काव्या मारन अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। दोनों ने 11 नवंबर 2026 को ग्रीस में एक निजी समारोह के दौरान शादी कर ली। इस खास मौके पर दोनों के परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त मौजूद रहे। शादी की खबर सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इस कपल को लेकर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि इस शादी में सबसे ज्यादा ध्यान जिस बात ने खींचा, वह था दोनों का शादी करने का अनोखा अंदाज।



अनिरुद्ध और काव्या की शादी पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह से काफी अलग रही। रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी में न तो कोई पंडित मौजूद था और न ही संस्कृत मंत्रों का उच्चारण किया गया। इतना ही नहीं, शादी में पारंपरिक फेरे और मंत्रोच्चार जैसी रस्में भी देखने को नहीं मिलीं। कपल ने अपने खास दिन को मॉडर्न अंदाज में सेलिब्रेट किया। हालांकि, इस दौरान भारतीय परंपरा से जुड़ी एक खास रस्म जरूर निभाई गई, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।

शादी में पारंपरिक मंगलसूत्र की रस्म निभाई गई। इस दौरान अनिरुद्ध रविचंदर ने अपने परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में काव्या मारन के गले में मंगलसूत्र पहनाया। इसके बाद वहां मौजूद परिवार के लोगों ने दोनों को नए जीवन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद दिया। बिना पंडित और पारंपरिक मंत्रों के हुई इस शादी में मंगलसूत्र की रस्म का शामिल होना चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग कपल के इस अनोखे वेडिंग स्टाइल को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

इस शादी में सिर्फ दूल्हा-दुल्हन का अंदाज ही नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों के लुक भी चर्चा में रहे। खासतौर पर अनिरुद्ध रविचंदर की मां की साड़ी ने लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने इस खास मौके पर ऐसी साड़ी पहनी थी, जिस पर हिंदू देवी-देवताओं की आकृतियां और डिजाइन बने हुए थे। उनका यह पारंपरिक लुक शादी के मॉडर्न अंदाज के बीच भारतीय संस्कृति की झलक पेश करता नजर आया।

ग्रीस में आयोजित इस निजी शादी समारोह में सिनेमा, राजनीति और बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत अपनी पत्नी लता रजनीकांत और बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत के साथ समारोह में पहुंचे। वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी अपनी पत्नी दुर्गा स्टालिन के साथ नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे।

नमिता थापर ने रामायण की उर्मिला की तुलना हाउसवाइफ से की

रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् ने जहां एक तरफ जमकर तारीफें बटोर ली है और बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ा दिया है वहीं दूसरी तरफ फिल्म को लेकर कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। शार्क टैंक इंडिया की जज नमिता थापर ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की तुलना आज की होममेकर्स से की है। उन्होंने लिंक्डइन पोस्ट में अपनी मां के त्याग को याद करते हुए बताया है कि कैसे घर संभालने में अपनी जिंदगी लगा देने वाली महिलाओं के योगदान को अक्सर पहचान नहीं मिलती।



नमिता ने अपने इस पोस्ट का टाइडल अनएप्रिशिएटेड हाउसवाइव्स लिखा है और ये उस अनुभव के बाद के विचार हैं जो हाल ही में रामायणम् देखने के बाद आया। उन्होंने माना कि शुरू में उन्हें लक्ष्मण की पत्नी का नाम याद नहीं आ रहा था और बताया कि उनके त्याग को बहुत कम ही आंका जाता है। अपने मन की बात सबके सामने रखते हुए उन्होंने लिखा, कल शाम मैंने थिएटर में रामायण देखी। पहले सोचा, मुझे लक्ष्मण की पत्नी (उर्मिला) का नाम नहीं पता। उनके त्याग का कभी जिक्र नहीं होता या उनकी तारीफ नहीं होती। आज भी हमारी सभी हाउसवाइव्स की यही हालत है। नमिता थापर ने अपनी मां के बारे में लिखते हुए कहा कि उनकी शादी 19 साल की उम्र में हो गई थी और 21 साल की उम्र में उन्होंने उन्हें (नमिता) को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि उनकी मां एयर होस्टेस बनना चाहती थीं और दुनिया घूमना चाहती थीं, लेकिन शादी के बाद उन्होंने यह सपना छोड़ दिया। इसी के साथ उनकी मां ने फ्रेंच में ड्रू की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी थी।

अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए नमिता ने लिखा, मुझे याद है कि स्कूल से घर आने पर वह मुझे गर्मजोशी से गले लगाती थी और मेरे लिए हमेशा नाश्ता तैयार रखती थीं। उन्होंने इसी पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि कैसे कामकाजी औरतों की तुलना में उनकी मां के पास खाली समय होने की वजह से उन्हें ताना सुनना पड़ता था। इनफैक्ट याद करते हुए उन्होंने माना कि इसे लेकर उन्होंने भी टीनेजर में मां से सवाल किए थे। उन्होंने लिखा, मैंने मां से कहा था कि अगर आपके पास इकनमा खाली समय है तो आपने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया।

सोनिया गांधी की किताब पर बनेगी तेलुगू फिल्म



सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव लगातार सुर्खियों में है। 10 नवंबर को यह संस्मरण रिलीज हुई और इसके बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों में इसके किस्से तैर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच यह घोषणा भी हो गई है कि इस किताब पर फिल्म बनेगी। जी हां, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने गुरुवार को घोषणा की कि सोनिया गांधी के संस्मरण 'Belonging: A Journey of Love' पर एक तेलुगू फीचर फिल्म बनाई जाएगी। इसमें उनके जीवन और राजनीतिक सफर को दिखाया जाएगा।

सोनिया गांधी का यह संस्मरण 544 पन्नों का है। कांग्रेस नेता ने इसमें अपने निजी जीवन से लेकर पारिवारिक अनुभव, राजीव गांधी से पहली मुलाकात, शादी और भारतीय राजनीति में उनके विदेशी मूल पर लगातार उठने वाले सवालों को लेकर बात की है। किताब में 2004 में प्रधानमंत्री पद को ठुकराने से लेकर कैंसर से लड़ाई और देश की कुछ सबसे प्रमुख घटनाओं; 1975 की इमरजेंसी, 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस पर उनकी टिप्पणियां शामिल हैं।

बहरहाल, गुरुवार को जग्गा रेड्डी में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान इस किताब पर फिल्म बनाने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने संगारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आगे आने और फिल्म के निर्माण में योगदान देने की अपील भी की। लगे हाथ निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस संयोजक जुलाकंती अंजनेयुलु ने फिल्म के निर्माण के लिए 2 करोड़ का योगदान देने की घोषणा की। जग्गा रेड्डी ने इस फिल्म के निर्माण के लिए 50 सदस्यों की एक समिति बनाने का सुझाव दिया, जिसकी देखरेख गांधी भवन के जनसंपर्क अधिकारी हरिप्रसाद करेंगे। उन्होंने पार्टी नेताओं से फंड जुटाने को कहा और कार्यकर्ताओं से बोले, आप लोग चुनावों में खर्च करते हैं, है ना? इसे भी वैसा ही एक खर्च मानिए।

आइए, बजट जुटाते हैं और एक अच्छा निर्देशक चुनते हैं। जब तैयारियां पूरी हो जाएंगी, तो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और TPCC अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ को फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए आमंत्रित करेंगे। जग्गा रेड्डी ने आगे यह भी कहा कि सोनिया गांधी की आत्मकथा की प्रतियां मंगवाई जाएंगी और उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बांटा जाएगा, ताकि वे उनके जीवन और अनुभवों को और बेहतर ढंग से समझ सकें। राजनेता ने बताया कि फिल्म में सोनिया गांधी के जीवन के विभिन्न चरणों को दिखाया जाएगा, जिसमें इंदिरा गांधी की बहू, राजीव गांधी की पत्नी, और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी की मां के रूप में उनकी भूमिकाएं शामिल होंगी।

सेट पर ही कार्तिक ने बहन संग मनायी भाई दूज

कार्तिक आर्यन के लिए इस बार भाई दूज का त्योहार थोड़ा खास रहा। फिल्म की शूटिंग के बीच कार्तिक ने बहन डॉ. कृतिका तिवारी के साथ त्योहार मनाने के लिए वक्त निकाला। खास बात यह रही की कार्तिक की बहन खुद उनसे मिलने उनके सेट पर पहुंच गईं। इसके बाद दोनों ने साथ में कुछ प्यारी तस्वीरें भी क्लिक की, जिन्हें कार्तिक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। तस्वीरों के साथ लिखे मजेदार कैप्शन ने भी सब का ध्यान खींचा जिसने त्योहार में हंसी का तड़का लगा दिया। भूल भुलैया 2 एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस के साथ भाई दूज सेलिब्रिशन के खास पल शेयर किए।



शादी के बाद करोड़ों के घर में शिफ्ट हुईं पलक पुरसवानी

पलक पुरसवानी शादी के बाद लैविश लाइफ जी रही हैं। लेकिन उनका खुद का एक आलीशान घर होने का सपना था। एक्ट्रेस का ये सपना अब पूरा हो गया है। पति रोहन खन्ना संग वो नए घर में शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन अभी घर में सामान सेट होना बाकी है। पलक ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो पति संग नए घर में खाना खा रही हैं। चारों तरफ कार्टन रखे हैं। अभी घर का सामान फैला हुआ है। पलक ने इंस्टा पोस्ट में बताया कि करीबन 10 महीने की प्लानिंग, इंतजार, हजारों फैसलों के बाद उनका घर तैयार हुआ है। आज वो अपने नए घर में बैठकर पहली मील खा रही हैं। वो कहती हैं- हमारे चारों तरफ कार्टन रखे हुए हैं। कोई भी कोना अभी सजा हुआ नहीं है। लेकिन उनका दिल सपने के साकार होने पर भर आया है।



छठ के घाटों को लेकर दिल्ली से मुंबई तक सियासी महाभारत

उप्र की चुनावी राजनीति को महाराष्ट्र और मुंबई में नहीं लाना चाहिए : राउत

» रेखा सरकार के मंत्री ने आप पर लगाए आरोप

» यूबीटी शिवसेना ने फणनवीस सरकार पर किया हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। छठ की घाटों को लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक सियासी महाभारत शुरूहो गई हें। जहां देश की राजधानी में यमुना में मरी हुई मछलियों पर बवाल हो गया है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने आप पर आरोप लगाया है कहा कि छठ पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना में मरी हुई मछलियां डालने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है, ताकि छठ पर्व से पहले माहौल खराब किया जा सके। उधर मुंबई में छठ पूजा के आयोजन और रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाने को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है।

यूबीटी शिवसेना, मनसे और कांग्रेस ने प्रदूषण रोकने के लिए कृत्रिम तालाबों की मांग की और गानों का विरोध किया। वहीं, सत्तारूढ़ दलों ने विपक्ष पर मराठी बनाम गैर-मराठी बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया। यूबीटी शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को महाराष्ट्र और मुंबई में नहीं लाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों के कारण रेलवे स्टेशनों पर हिंदी और भोजपुरी गाने बजाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली, क्रिसमस और ईद जैसे त्योहारों के दौरान ऐसा कभी नहीं किया गया था। राउत ने कहा कि रेलवे की घोषणाओं का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को ट्रेनों और उनके समय-सारणी के बारे में जानकारी देना होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी को लोगों के छठ पूजा मनाने से कोई आपत्ति नहीं है और हर किसी का एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होने के लिए स्वागत है। हालांकि, उन्होंने धार्मिक आयोजनों के राजनीतिकरण की आलोचना की।





क्या विपक्ष आसुरी शक्तियों में बदल गया है : आनंद दुबे

शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि दिवंगत शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे खुद छठ पूजा के भव्य आयोजन का समर्थन करते थे, लेकिन उनके ही उत्तराधिकारी अब हिंदू त्योहारों का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के रुख पर सवाल उठाते हुए दुबे ने पूछा कि क्या हिंदू त्योहारों और देवी-देवताओं का विरोध करके विपक्ष एक आसुरी शक्ति बन गया है? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या विपक्ष की आपत्तियों का संबंध आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों से है, और क्या समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इन विरोध-प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं?

यमुना में सैकड़ों मरी हुई मछलियां तैरती हुई दिखीं : भारद्वाज

वजीराबाद पुल के नजदीक यमुना में सैकड़ों मरी हुई मछलियां तैरती हुई दिखी है, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आप कार्यकर्ता महेश आर्या ने वीडियो बनाकर आरोप लगाया कि यमुना को साफ दिखाने के लिए केमिकल डाला गया, जिससे मछलियां मर गईं। वहीं दिल्ली में आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी वीडियो पोस्ट कर लिखा अगर यह पानी मछलियों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो इंसानों के लिए कैसे सुरक्षित है?

सोची-समझी साजिश के तहत यमुना को प्रदूषित किया जा रहा : प्रवेश वर्मा

दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी आमने-सामने है। आप इसे यमुना का प्रदूषण बता रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार के मंत्री दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रवेश वर्मा ने इसे आप की सोची-समझी साजिश करार दिया है, प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि आप के लोग बाजार से मरी हुई मछलियां खरीदकर यमुना में डाल रहे हैं और वीडियो बनाकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं।

आशीष ने शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की

महाराष्ट्र के वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने एकता की अपील करते हुए कहा कि आपसी विवादों में उलझने के बजाय, हमारा ध्यान एक विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र बनाने पर होना चाहिए। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि हर समुदाय को अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करते समय दूसरों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी समुदायों को ध्वनि संबंधी पाबंदियों और अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। कृत्रिम तालाबों की मांग पर भोयर ने कहा कि कानून के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

पंत पहले टेस्ट के लिए फिट

» टेस्ट सीरीज से पहले भारत को मिली बड़ी राहत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। फिटनेस को लेकर हफ्तों तक चली अनिश्चितता के बाद ऋषभ पंत गुरुवार को न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। वह शुक्रवार को वेलिंगटन में भारतीय टेस्ट टीम से जुड़ेंगे, जहां 19 नवंबर से सीरीज की शुरुआत होनी है। पंत साइड स्ट्रेन से उबर रहे थे और उन्हें बीसीसीआई की मेडिकल टीम से फिटनेस क्लीयरेंस मिल गई है। जानकारी के अनुसार, बंगलूरू स्थित सीओई में लंबे समय तक रिहैब प्रोग्राम पूरा करने के बाद, मेडिकल टीम से मंजूरी मिलने पर पंत गुरुवार सुबह न्यूजीलैंड के लिए निकल गए। सूत्र ने बताया, पंत आज सुबह न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुए और सिंगापुर से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए वहां पहुंचेंगे।

माना जा रहा है कि वह सिंगापुर से भी निकल चुके हैं। न्यूजीलैंड के समय के अनुसार वह सुबह जल्दी और भारतीय समय के अनुसार तड़के वेलिंगटन पहुंच जाएंगे। पंत ने इंस्टाग्राम पर फ्लाइट की फोटो भी शेयर की है। पंत एक से चार अक्तूबर के बीच श्रीनगर में शेष भारत टीम की कप्तानी करते हुए ईरानी कप के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वह 23 अक्तूबर से बंगलूरू स्थित बीसीसीआई के सीओई में रिहैब से गुजर रहे थे। जब वह सीओई पहुंचे थे, तब तक उन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम और टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन चार दिवसीय मैचों के लिए इंडिया ए टीम में भी चुन लिया गया था। हालांकि, उनका खेलना फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर निर्भर था। पंत 19 नवंबर से वेलिंगटन टेस्ट खेलने को लेकर आश्वस्त होंगे, लेकिन उनका देर से पहुंचना टीम मैनेजमेंट के सामने एक सवाल खड़ा करता है। क्या वे प्लेइंग-11 में पंत और ध्रुव जुरेल दोनों को चुनेंगे, जिन्होंने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ इंडिया ए की कप्तानी की थी? या फिर वे दोनों विकेटकीपरों में से केवल एक को चुनेंगे और इसके बजाय साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दोनों को मौका देंगे? जुरेल ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ चार पारियों में एक शतक और एक अर्धशतक बनाया था, जबकि साई सुदर्शन के नाम पांच पारियों में 91 और 88 के स्कोर थे और पडिक्कल ने भी पांच पारियों में 199 और 80 रन बनाए थे।



अंडर-19 एशिया कप: फाइनल में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान

अल अमेरात। भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को आठ विकेट से हरा दिया। भारत का 14 नवंबर को होने वाले फाइनल में सामना गत चैंपियन पाकिस्तान से होगा। अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम का दबदबा है। भारत ने अंडर-19 एशिया कप रिकॉर्ड आठ बार जीता है, जिसमें एक संयुक्त खिताब भी शामिल है। भारतीय टीम ने 1989, 2003, 2012, 2013-14, 2016, 2018, 2019 और 2021 में खिताब अपने नाम किया था। इसके अलावा टीम दो बार 2024 और 2025 में उपविजेता रही है। भारत को पिछली बार फाइनल में पाकिस्तान से ही हार का सामना करना पड़ा था। अब टीम इंडिया के पास पिछली हार का बदला चुकता करने का मौका होगा। भारत को इस टूर्नामेंट में एकमात्र हार पाकिस्तान से ही मिली थी। अब ये दोनों टीमें एक बार फिर खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी।

कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा

» फारूक बोले- पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे इससे कुछ हासिल नहीं होगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत फिर शुरू करने की जोरदार पैरवी की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विवादों का समाधान गोलियों और सैन्य टकराव से नहीं हो सकता। अगर दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए सभी ओर से गोलीबारी बंद होने का इंतजार किया जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। हालांकि, उन्होंने पाकिस्तान से साफ कहा कि उसे पहले आतंकवाद बंद कर बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाना होगा।

गुरुवार को जम्मू में पूर्व सूचना अधिकारी मदन मंटू के परिवार से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में फारूक ने कहा कि वह हमेशा पाकिस्तान से आतंकवाद बंद करने की अपील करते रहे हैं। आतंकवाद से कुछ हासिल नहीं हो सकता। बातचीत की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता केवल संवाद से ही निकल सकता है। भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इस रुख पर कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते, फारूक ने कहा, अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि जब तक सभी की गोलियां बंद होंगी, तब तक रात हो जाएगी। उनका कहना था कि युद्ध और सैन्य टकराव केवल तबाही लाते हैं। उन्होंने ईरान और यूक्रेन में जारी विनाश का उदाहरण देते हुए कहा कि स्थायी समाधान बातचीत और आपसी संवाद से ही संभव है। फारूक ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को फिर से सक्रिय करने की भी पैरवी की।



कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर जताई चिंता

कुलगाम और किश्तवाड़ में हाल में हुए आतंकी हमलों पर फारूक ने चिंता जताई। इन घटनाओं में दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की हत्या हुई, जबकि तीन सीआरपीएफ जवान घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर को हासिल करने का सपना देखने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद से उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। हालांकि, उन्होंने दिल्ली में आतंकवाद खत्म होने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाल की घटनाएं बताती हैं कि जम्मू-कश्मीर में अब भी आतंकवाद का खतरा बना हुआ है। इसे खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसी घटनाएं अब भी हो रही हैं। कोई नहीं जानता कि अगला हमला कहां हो जाए।

जदयू में सिर्फ नीतीश गुट सभी एकजुट : लेसी सिंह

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

किशनगंज। बिहार सरकार की भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने सुशासन दिवस-नीतीश संवाद की तैयारियों को लेकर बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि पहले बिहारी कहलाना गाली माना जाता था, लेकिन आज बिहारियों को सम्मान दिलाने का काम नीतीश कुमार ने किया है।

उन्होंने बिजली, सड़क और पानी सहित राज्य में हुए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बेहद शालीन व्यवहार वाले नेता हैं। तेजस्वी यादव के निशांत को मुख्यमंत्री बनाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वे अपनी पार्टी संभालें, निशांत जी की चिंता न करें। वहीं, जदयू में दो गुट होने की बात पर उन्होंने कहा कि जदयू में सिर्फ एक ही गुट है-नीतीश गुट। सभी लोग एकजुट हैं।

सैम पित्रोदा ने की मोदी की तारीफ तो मचा सियासी घमासान

» प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी को दी नसीहत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत रूप से तारीफ की है और उन्हें गुजराती मित्र बताया है। साथ ही पित्रोदा ने कहा कि एक इंसान के तौर पर वे मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और उनके बीच कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। अब पित्रोदा की इस तारीफ पर सियासी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) की नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है।

प्रियंका ने सैम पित्रोदा द्वारा पीएम की तारीफ करने के बाद एक राजनीतिक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा सोचती हूं कि सोशल मीडिया की ट्रोल गैंग/'अनौपचारिक' सपोर्ट सिस्टम इस पर क्या कहेगा? मुझे भी उनके इस 'प्यार' का सामना करना पड़ा है, उम्मीद है कि वे अपने ही किसी व्यक्ति पर भी ऐसा ही 'प्यार' बरसाएंगे। बता दें पित्रोदा ने कहा कि मेरी पत्नी और मैं उनसे मिल चुके हैं। व्यक्तिगत स्तर पर वे बहुत ही आत्मीय, दयालु, स्नेही और परवाह करने वाले रहे हैं। इसी तरह, मैं गुजरात में उनके घर भी कई बार जा चुका हूं। हमारे बीच कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं हैं।



हिमाचल में हलचल, बारूदी तापमान सुलगता लद्दाख!

सोनम वांगचुक हाउस अरेस्ट सड़कों पर उतरे लोग

» क्षेत्रीय असंतोष से आगे बढ़कर केंद्र के साथ बड़े राजनीतिक टकराव में बदलता आंदोलन

» दिसंबर में चुनाव कराने पर बवाल, लेह से कारगिल तक विरोध की आवाज

» पिछले साल चार मौतों की जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग भी अधर में

» हो रहे चुनाव को वांगचुक ने बताया नकली काउंसिल इलेक्शन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

शिमला। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक बार फिर सियासत का तापमान उबाल पर है। लद्दाख की वादियों में सिर्फ सर्द हवाएं नहीं चल रहीं बल्कि लोकतंत्र अधिकार और जवाबदेही को लेकर उठे सवालों का तूफान खड़ा हो गया है। सोनम वांगचुक के घर के बाहर हथियारबंद जवानों की तैनाती उनकी आवाजाही पर 60 दिनों की पाबंदी और सड़कों पर उतरते लोग। यह तस्वीर उस लद्दाख की है जिसे कभी शांतिप्रिय सीमांत क्षेत्र बताकर देश के सामने पेश किया जाता रहा। अब वही लद्दाख पूछ रहा है कि आखिर उसकी आवाज सुनने के बजाय उसे रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है?

सरकार को दिसंबर में चुनाव कराने की जल्दी है। प्रशासन का तर्क है कि समय पर चुनाव होंगे तो निर्वाचित परिषदें बनेंगी लोकतंत्र मजबूत होगा और विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन लद्दाख के लोगों का सवाल है कि जिस चुनाव में बर्फीले मौसम के कारण हजारों मतदाताओं के अपने घरों से दूर रहने की आशंका है वह लोकतंत्र को मजबूत करेगा या मताधिकार को कमजोर? जबकि स्थानीय संगठन मार्च-अप्रैल में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं तब दिसंबर की तारीख पर इतनी जिद क्यों है। लददाख का असंतोष अचानक पैदा नहीं हुआ है 24 सितंबर 2025 को लेह में हुए हिंसक घटनाक्रम में चार लोगों की मौत हुई थी। जांच आयोग बना बयान दर्ज हुए लेकिन एक साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया वह जवाब मांग रहे हैं जिन लोगों ने राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग उठाई वही लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं संवाद की मेज पर बैठने वाले संगठन अब सड़कों पर हैं और उनके प्रमुख चेहरों में शामिल सोनम वांगचुक की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है।

सरकार कह सकती है कि कानून-व्यवस्था सर्वोपरि है। बिल्कुल है। चुनाव शांतिपूर्ण होने चाहिए हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून-व्यवस्था का मतलब यह भी तो है कि जनता के सवालों का जवाब मिले जांच रिपोर्ट सामने आए और लोकतांत्रिक असहमति को अपराध की तरह न देखा जाए। लोकतंत्र में सरकारें सवालों से नहीं जवाबों से मजबूत होती हैं। अगर हर असुविधाजनक सवाल के सामने पहरा खड़ा कर दिया जाएगा तो फिर संवाद किससे होगा। लद्दाख का मामला अब सिर्फ एक कार्यकर्ता की आवाजाही पर लगी पाबंदी का नहीं रह गया है। यह केंद्र और सीमांत क्षेत्र के बीच भरोसे की परीक्षा बनता जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फ जम सकती है रास्ते बंद हो सकते हैं लेकिन लोगों के भीतर जमा असंतोष को आदेश जारी करके नहीं पिघलाया जा सकता। दिल्ली को तय करना होगा कि उसे लद्दाख में सिर्फ चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी है या वहां के लोगों का भरोसा भी जीतना है। क्योंकि सरहद की सुरक्षा सिर्फ जवानों की चौकसी से नहीं सरहद पर रहने वाले नागरिकों के विश्वास से भी मजबूत होती है।



आठ परिषदें, सौ निर्वाचन क्षेत्र और परिसीमन का विवाद

इस बार लद्दाख की चुनावी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रशासन ने परिसीमन के बाद आठ परिषदों के लिए कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए हैं। पहले लेह और कारगिल की दो परिषदों में 26-26 निर्वाचित सदस्य होते थे। अब आठ जिलों के लिए सीटों का नया ढांचा तैयार किया गया है। कुल 100 सीटों में 36 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रशासन इसे स्थानीय लोकतंत्र के विस्तार और प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में कदम बता रहा है। लेकिन स्थानीय संगठनों को परिसीमन की प्रक्रिया पर आपत्ति है। उनका आरोप है कि नई सीटों का निर्धारण करते समय पर्याप्त संवाद और स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा गया। कुछ संगठनों ने मतदाता सूचियों की व्यापक समीक्षा और सभी पक्षों से बातचीत की मांग भी की है। और यही कारण है कि विरोध केवल चुनाव की तारीख तक सीमित नहीं है। स्थानीय समूहों को आशंका है कि यदि परिसीमन और चुनावी प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों का समाधान किए बिना मतदान कराया गया तो नई परिषदों की वैधता और प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद बना रहेगा।प्रशासन का दावा है कि नई परिषदों से लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार होगा। लेकिन जनता के एक हिस्से का सवाल है कि प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से क्या वास्तविक अधिकार भी बढ़ेंगे? यदि परिषदें स्थानीय जरूरतों के मुताबिक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने से जनता की अपेक्षाएं पूरी कैसे होंगी?

चुनाव चार दिसंबर को, विरोध अभी से क्यों?

लद्दाख में इस समय सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के चुनाव को लेकर है। प्रशासन ने सभी आठ लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के चुनाव की प्रक्रिया घोषित की है। मतदान चार दिसंबर को होगा और पूरी चुनावी प्रक्रिया आठ दिसंबर तक पूरी की जानी तय है। स्थानीय संगठनों को चुनाव कराने पर आपत्ति नहीं बल्कि चुनाव के समय और परिसीमन की प्रक्रिया पर है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस चाहते हैं कि चुनाव सर्दियों के बजाय मार्च-अप्रैल में कराए जाएं। उनका तर्क है कि दिसंबर में लद्दाख का मौसम बेहद कठोर होता है। तापमान कई इलाकों में शून्य से काफी नीचे चला जाता है भारी बर्फबारी से सड़कें बंद हो सकती हैं और दूरदराज के गांवों तक पहुंचना कठिन हो सकता है। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने भी उपराज्यपाल को पत्र लिखकर चुनाव टालने की मांग की है। उनका कहना है कि सर्दियों में विद्यार्थी, बुजुर्ग, व्यापारी और दूसरे नागरिक बड़ी संख्या में जम्मू, श्रीनगर और अन्य गर्म इलाकों की ओर चले जाते हैं। स्थानीय नेताओं के मुताबिक आबादी का लगभग 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा सर्दियों में क्षेत्र से बाहर हो सकता है। ऐसे में मतदान की तारीख तय करते समय मतदाताओं की वास्तविक उपलब्धता पर विचार होना चाहिए।

लेह और कारगिल की साझा नाराजगी आंदोलन का बढ़ा दायरा

लद्दाख की राजनीति में लेह और कारगिल की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग रही हैं। लेकिन राज्य का दर्जा संवैधानिक सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों के सवाल पर दोनों क्षेत्रों के संगठनों ने मिलकर आवाज उठाई है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इस आंदोलन के प्रमुख मंच हैं। ताजा चुनावी विवाद में भी दोनों की आपत्तियां सामने आई हैं। कारगिल में बंद लेह में विरोध और चुनाव बहिष्कार की घोषणाएं इस बात का संकेत हैं कि असंतोष किसी एक शहर या एक नेता तक सीमित नहीं है। इस बार विवाद का दायरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसमें स्थानीय राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, सामाजिक समूह, व्यापारिक समुदाय और जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। सांसद हनीफा जान ने चुनाव टालने की मांग की है। लेह के संगठनों ने परिसीमन और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वांगचुक ने राज्य के दर्जे संवैधानिक सुरक्षा और जांच रिपोर्ट के मुद्दे को फिर से उठाया है।

वांगचुक का सोशल मीडिया पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनम वांगचुक ने कहा कि उनके घर के आसपास दर्जनों हथियारबंद गार्ड तैनात किए गए हैं उन्होंने ऑफिशियल दावों को गलत बताया कि उन्हें सिर्फ घर के अंदर रहने की सलाह दी गई थी। वांगचुक ने पोस्ट किया, मैं हाउस अरेस्ट में हूं। दर्जनों हथियारबंद गार्ड मेरे घर को घेरे हुए हैं, जबकि सरकारी वर्जन कहता है, मुझे घर पर रहने की सलाह दी गई है। यह सब अजीब सवाल पूछने के लिए है, जैसे कि ज्यूडिशियल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट (पिछले साल लेह में हुई हत्याओं की) में देरी क्यों हो रही है और सर्दियों के बीच में लोगों पर एक नकली काउंसिल इलेक्शन क्यों थोपा जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर प्रहार

» आरोपों पर भाजपा ने किया पलटवार

» कांग्रेस सांसद ने लगाया आरोप, कहा-उनका फोन टैप करवाया जा रहा

» फोन दिखाकर बोले-ये देखो मेरा फोन टैप किया जा रहा, सारे सबूत इसी में हैं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। एकबार फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद ने शुक्रवार को एक बड़ा आरोप लगाया है, राहुल ने दावा किया है कि उनका फोन टैप करवाया जा रहा है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा मेरे सभी आरोपों का सबूत मेरे फोन में है, जिसे प्रधानमंत्री ने टैप कर रखा है. आमने-सामने की बहस से यह साबित हो जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहा है, कौन देशद्रोही है, वह कब से देशद्रोही है, और ऐसी कई अन्य बातें जो मुझे पता हैं और मेरे फोन में मौजूद हैं, राहुल गांधी के इस दावे के बाद राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है, इस दावे के साथ ही उन्होंने फिर से बहस की चुनौती भी दी है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर किया दावा

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए यह दावा किया है कि उनका फोन टैप करवाया जा रहा है. क्योंकि मैं जो भी आरोप लगा रहा हूं उनके सारे सबूत मेरे फोन में हैं. लेकिन मैं पीएम मोदी से वन-ऑन-वन बहस से यह साबित हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है. वन-ऑन-वन बहस से यह साबित हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है, देश विरोधी कौन है और कब से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है. ऐसी कई दूसरी जानकारियां भी हैं, जो मुझे पता हैं और मेरे फोन में मौजूद हैं।



राहुल ने कहा कि कृपया किताब पर और टिप्पणी करें, जितना बयान देंगे, उतना अच्छा रहेगा, थैंक्यू : नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी की किताब की आलोचना किए जाने पर तंज किया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा कि अच्छी किताब है। वो सभी पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि वो इसपर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को इंस्टाग्राम स्टोरी में वीडियो शेयर कर कहा, असल बात है कि कई गुप्त रूप से वो पसंद भी करते हैं और मानते हैं कि अच्छे हैं। दुर्भाग्य से वो ये कह नहीं सकते हैं भक्त कृपया किताब पर टिप्पणी करें, जितना बयान देंगे, उतना अच्छा रहेगा। थैंक्यू सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग ए जर्नी ऑफ लव 10 नवंबर को लॉन्च हुई है।

अपना मानसिक परीक्षण करवाएं राहुल : राजीव



केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने फोन टैपिंग के दावे को खारिज करते हुए कहा, राहुल गांधी से मैं पूरे सम्मान के साथ बस इतना ही कह सकता हूं कि उन्हें अपना मानसिक परीक्षण करवाना चाहिए। कोई भी उनके फोन को टैप करने की जहमत नहीं उठा रहा है। किसी को भी उनके फोन को टैप करने में दिलचस्पी नहीं है। अगर किसी को दिलचस्पी है भी, तो सिर्फ यह समझने में कि उनका दिमाग दिन-प्रतिदिन झूठ पर ही क्यों चलता है।भाजपा ने इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहस करने की राहुल की मांग को खारिज कर दिया था।

महाराष्ट्र कार्यालय:- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। विधि सलाहकार: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा